ज. बंजीत सिंह, न्यायाधीश

बलबीर सिंह,–प्रार्थी

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य –उत्तराधीनी

सीडब्ल्यूपी संख्या 11434/2009

26 अक्टूबर, 2010

भारतीय संविधान, 1950–कला. 226–हरियाणा सिविल सेवाएं (दंड और अपील) नियम, 1987–नियम 7–किसी कार्यकारी अभियंता के खिलाफ झूठा डिप्लोमा और एएमआईई डिग्री प्रस्तुत करने के आरोप–आपराधिक मामला का पंजीकरण–विभागीय प्रक्रिया भी प्रारंभ–जाँच रिपोर्ट ने प्राथमिकताओं पर आधारित पेटीशनर को दोषी ठहराया– सेवा से बर्खास्ती का दंड–नियम 7 द्वारा प्रदान किया गया है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रमुख दंड लगाने का कोई आदेश उसको उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करने के लिए उसे एक योग्यता देने के बिना किया जा सकता है। इस नियम के तहत यह प्रदान किया गया है कि इन नियमों के लागू होने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रमुख दंड लगाने का कोई आदेश उसे उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करने के लिए उसे एक योग्यता देने के बिना किया जा सकता है। इस नियम में प्रदान किया गया है कि जो व्यक्ति किसी भी आरोप के खिलाफ आरोपित किया जाता है, उसे इन आरोपों में से किसी भी को स्वीकृत नहीं करता है तो उसे लिखित रूप से अब यह कहने के लिए समय दिया जाना चाहिए कि उसने सभी या किसी भी आरोपों की सच्चाई को माना है और उसके पास यदि कोई व्याख्या या स्वरक्षण है तो वह क्या है। दोषी कर्मचारी से यह भी पूछा जाता है कि क्या उसे व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करना है। अगर व्यक्ति की व्याख्या से प्राधिकृत अधिक नहीं हैं, तो प्राधिकृत अधिकारी एक जाँच का निर्देश करेगा, जिसमें ऐसे आरोपों के रूप में सुना नहीं गया होता है जो स्वीकृत नहीं हैं। आरोपित व्यक्ति को साक्षात्कार करने का इच्छा भी होनी चाहिए। प्राधिकृतता द्वारा दी गई व्यक्ति की व्याख्या से संतुष्ट नहीं होने पर, उन्हें एक जाँच का निर्देश दिया जाएगा, जिसमें उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं स्वीकृत किए गए आरोपों के रूप में सभी साक्षात्कार सुने जाएँगे। आरोपित व्यक्ति को साक्षात्कारय में साक्षात्कार करने, साक्षात्कार में व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करने और जो कोई उन्हें चाहिए, उन्हें बुलाया जाना चाहिए, यह भी स्वीकृत है, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप से किसी भी साक्षात्कारय को बुलाने से इनकार किया जाता है। महत्वपूर्ण है कि प्रक्रिया में पूर्वपक्ष के तरीके और उनके आवेग की एक पर्याप्त रेकॉर्ड होना चाहिए। आरोपित व्यक्ति को यह भी अनुमति है कि वह सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की सहायता प्राप्त करें,

यदि उसे ऐसा इच्छा है। इस प्रकार, प्रदान किए गए नियम 7 में विस्तृत प्रक्रिया को पहले इंपोज करने से पहले अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना चाहिए। जाँच अधिकारी ने नियम 7 में दी गई प्रक्रिया का पालन करना नहीं किया है और विशेषत: प्रदान किए गए नियमों के तहत दोषी कर्मचारी को उसके आत्मरक्षण के लिए कोई अवसर नहीं दिया गया है। जिस शक्ति की गई साक्षात्कार की रिकॉर्डिंग की गई थी, वह प्राथमिकताओं के बिना हुई थी और उसे किसी भी साक्षात्कार की घटनाओं के बारे में कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया गया था। नियमों के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की उल्लंघन की स्पष्ट घटना है और यह उल्लंघन प्राथमिकताओं के लिए प्रतिसाद में गंभीर नागरिक परिणामों का परिणाम है। प्राथमिकताओं के आधार पर प्राथमिकताओं से प्राथमिकताएँ नहीं फॉलो की गई थीं और इस उल्लंघन के कारण प्रयासरूप से प्रधिकृत आदेश को गलत ठहराया जाता है और वही. इस प्रकार, स्थिति को सहारा नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 15)

और यह भी निर्धारित किया गया कि प्राथमिकता के लिए प्राथमिकता और संगठन के प्रति निष्ठा को ध्यान में रखते हुए, यह उचित होगा कि प्रतिसादी को उस स्थान से जांच करने की अनुमति दी जाए जहां प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है और उसी के साथ जारी रखने की अनुमति दी जाए जिसमें प्राथमिकता को अपनी रक्षा करने के लिए प्राथमिकता को पर्याप्त और न्यायसंगत अवसर देने के साथ। जवाबदेही रखा जाएगा कि प्रतिसादी भी प्राथमिकताओं के समर्थन में उपयोग के लिए किसी भी साक्षात्कार को प्रवेश कराएं। प्राथमिकताओं को विचारित करने और उनके आधार पर आगे कृत्रिम कार्रवाई के लिए अनुमति दी जाएगी।

(पैरा 17)

जे. एस. माणिपुर, प्रार्थी के लिए।

हरियाणा राज्य के लिए हरिश राठी, सीनियर डीएजी, वकील। रणजीत सिंह, जे.

(1) प्रार्थी ने इस रिट प्रार्थना दायर की है ताकि 16/17 जुलाई, 2009 को उसके अस्तागत का आदेश को चुनौती देने के लिए। इस्तीन अस्तागत का आदेश 10 मार्च, 2006 को जांच रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था। प्राथमिकता की मुख्य शिकायत यह है कि इस मामले में की गई जांच 'हरियाणा सिविल सेवाएं (दंड और अपील) नियम 1987 के निर्बाध प्रावधानों का उल्लंघन था (संक्षेप में। 'नियम')। (2) प्राथमिकता के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा, से मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद, प्रार्थी ने 7 दिसम्बर, 1979 को पी.डब्ल्यू.डी. (बी एंड आर) विभाग में शामिल हो गए। 1984 में, प्रार्थी ने नाइट क्लासेस में भौतिक यान्त्रिकी में डिप्लोमा हासिल किया। इस डिप्लोमा के आधार पर, प्रार्थी को 3 नवंबर, 1986 को रोड इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नति मिली। 1988 में, प्रार्थी ने ए.एम.आई.ई. डिग्री पास की।

(3) 1992 में, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ सब डिविजनल इंजीनियर के पदों के लिए सीधी भर्ती के रूप में नियुक्ति के लिए विज्ञापन किया। प्रार्थी ने इसके लिए

आवेदन किया और उसे एस.डी.ओ. (पंचायती राज) के रूप में चयन किया गया। उसने 19 मई, 1993 को पद को संबोधित किया और 22 जुलाई, 1998 को कार्यपालिका इंजीनियर के रूप में पदोन्नति पाई। प्रार्थी को कार्यपालिका इंजीनियर के रूप में पदोन्नति करते समय, उसकी ए.एम.आई.ई. डिग्री को जाँचने के लिए प्राप्त की गई थी। हालांकि, प्रार्थी के अनुसार, उसे निर्दोष पाया गया था। फिर पुलिस को जाने वाले एक उपयोगकर्ता द्वारा शिकायत के आधार पर, प्रार्थी के डिप्लोमा और ए.एम.आई.ई. डिग्री की मानकता के संबंध में जांच की गई और फिर भी प्रार्थी को निर्दोष पाया गया। प्रतिसादी ने जिस दिन निर्दोष पाया था, उसी दिन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिनिधित्व करते हुए यह भी आपत्ति की थी कि जांच नहीं होगी। आखिरकार, 6 जनवरी, 2004 को एक झूठे डिप्लोमा और डिग्री प्रस्तुत करने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज किया गया था। समयानुसार, प्रार्थी को भी चार्जशीट दी गई थी जिसमें आलोचना थी कि प्रार्थी के डिप्लोमा और डिग्री झूठी थीं, जिससे एस.डी.ओ. पद पर नियुक्ति होने से Rs. 16,32,522.45 की आर्थिक हानि हुई थी।

(4) आरोप पत्र के जवाब में, प्रार्थी ने उत्तर सौंपा। उसने इसके दौरान विभागीय प्रक्रिया को रोकने की दुआ भी की थी जब क्रिमिनल केस पेंडिंग था। हालांकि, जांच अधिकारी को 21 सितंबर, 2005 को नियुक्त किया गया था। बाद में जांच अधिकारी बदला गया और प्रार्थी ने 12 जनवरी, 2006 को उसके सामने प्रकट होने का कारण दिया। प्रार्थी के अनुसार, उसे सही अवसर प्रदान किए बिना, जांच अधिकारी ने 10 मार्च, 2006 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया था कि प्रार्थी के खिलाफ आरोप साबित हो गए थे। इसके बाद प्रार्थी को एक दिखावा कारण सूचना सौंपी गई, जिसमें उसकी नौकरी से बर्खास्ती और राशि की वसूली के साथ सजा का प्रस्ताव किया गया। प्रार्थी ने अपनी उत्तर सौंपी 25 जनवरी, 2007 को, जिसमें उसने यह कहते हुए कि जांच पूरी तरह से प्रक्रिया और नियमों का उल्लंघन करके हुई थी, दर्ज किया। उसके उत्तर को मध्यस्थ करते हुए भी, प्रतिसादी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसने प्रार्थी को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया। प्रार्थी के अनुसार, उसको यह साबित करने का कोई भी अवसर नहीं मिला कि उसका डिप्लोमा और ए. एम. 1. ई. डिग्री जनूइन थीं और उन्हें झूठा नहीं ठहराया गया था, जैसा कि आरोपित किया गया था, और जांच अधिकारी का निर्णय केवल विजिलेंस द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर था, इसके बिना किसी समर्थन सामग्री के। प्रार्थी ने इस पर आपत्ति दर्ज करने के लिए इस रिट पिटीशन को दायर किया।

(5) प्रतिसादी की ओर से उत्तर-हस्ताक्षर किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि प्रार्थी को 19 मई, 1993 को एस. डी. ई. (पंचायती राज) के रूप में नियुक्ति मिली थी और उसे 22 जुलाई, 1998 को कार्यपालक अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया था। उत्तर में कहा गया है कि 2 जनवरी, 2004 को पुलिस मधुबन के एस.पी. (क्राइम) द्वारा की गई 1 दिसंबर, 2003 की जांच रिपोर्ट की एक प्रति प्रार्थी को प्रेषित की गई थी, जिसमें यह खुलासा हुआ था कि प्रार्थी द्वारा प्राप्त की गई डिप्लोमा और डिग्री प्रमाणपत्र झूठे थे। हालांकि, प्रार्थी

ने स्टेट के खिलाफ एक मानवाधिकार याचिका दाखिल की, जिसमें उसने यह दावा किया कि उसकी नौकरी से निलंबित करने का प्रयास किया गया था, जिसे उसने उच्च न्यायालय में लाखों रुपए के नुकसान का कारण बताया गया है। उत्तर में कहा गया है कि विभाग द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी को अनुसरण याचिका की गई थी और इस जाँच रिपोर्ट के अनुसार, प्रार्थी के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए थे। जांच रिपोर्ट के साथ सहमत होकर, दंडित प्राधिकृतिक द्वारा प्रार्थी को बर्खास्त करने का दंड प्रवद्ध किया गया।

(6) यह भी खुलासा है कि प्रार्थी की याचिका को विभागीय प्रक्रिया पेंडिंग क्रिमिनल प्रक्रिया के दौरान रोकने की 10 मार्च, 2008 को इसी न्यायालय द्वारा इनकार किया गया था, जो प्रार्थी द्वारा इस संबंध में दायर की गई सिविल रिट पिटीशन संख्या 3024 ऑफ 2006 को खारिज करते समय किया गया था।प्रार्थी ने इसी के खिलाफ एस.एल.पी. दायर की, जिसे उसने वापस लिया। इसके साथ ही, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलॉजी, सेक्टर 26, चंडीगढ़, से एक स्पष्टीकरण रिपोर्ट का संदर्भ दिया गया है, जिससे यह साफ हो रहा है कि विभाग ने प्रार्थी को कोई डिप्लोमा प्रमाणपत्र और विस्तृत अंक पत्र नहीं जारी किए थे। इसमें यह भी कहा गया है कि प्रमाणपत्र जाली हैं, क्योंकि कोई भी इस कॉलेज की प्राधिकृति ने ऐसे प्रमाणपत्र जारी नहीं किए थे। इसके अनुसार, कहा जा रहा है कि प्रार्थी ने झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करके नौकरी प्राप्त की है, जिससे सरकार को बड़ा हानि हुआ है। इसलिए यह याचिका की जाती है कि प्रार्थी को किसी भी सहायता का हक नहीं है।

(7) प्रार्थी के वकील ने मुख्य रूप से उस प्रति लगाए गए दंड का चुनौती देने का कारण बताया कि जाँच ने नियम 7 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पूरा उल्लंघन किया गया था। इस नियम का संदर्भ करके, वकील ने बातचीत करते समय दोषित कर्मचारी को यहां तक की अधिकार और आवश्यकताएँ हाइलाइट करेंगे जब जाँच की जाती है। वकील यह भी हाइलाइट करेंगे कि जाँच अधिकारी ने केवल निगरानी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो जाँच प्रक्रिया के सामने नहीं लाई और साबित नहीं की गई थी। वकील के अनुसार, यह एक्स पार्टे जाँच थी, जिसमें प्रार्थी को यह साबित करने के लिए कोई अवसर नहीं मिला कि उसके पास जो डिग्री थी, वह झूठी नहीं थी। जाँच प्रक्रिया की प्रतिलेख भी जाँच पदाधिकारी द्वारा किए गए बिना साक्षात्कार के और बिना प्रक्रियाकारी आवश्यकताओं का पालन किए हुए सिर्फ रिपोर्ट देने के बारे में साबित होने के लिए रिकॉर्ड पर डाला गया है।

8) तर्कशास्त्र के दौरान, राज्य के वकील ने एकाधिक अवस्थाओं में यह सुनिश्चित करने के लिए समय लिया कि क्या आपत्तियों का कोई साक्षात्कारधारित किया गया था जो दिखा गया कि प्रार्थी द्वारा प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा जाली थी या यह उपविगिलेंस जाँच में रेलायंस केवल इस बारे में किया गया था, जो बजाय एक योग्य साक्षात्कारधारी साक्षात्कारधारी के माध्यम से और आधिकारिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। हरियाणा सरकार के के अंतर्गत एक उप सचिव के द्वारा बनाई गई एक शपथपत्र की रजिस्ट्री तारीख 11 अगस्त, 2010 को की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि जाँच के प्रक्रिया के दौरान, सुपरिंटेंडेंट पुलिस, सी.आई.डी. हरियाणा,

की जाँच रिपोर्ट और संस्थान से प्राप्त पत्र / संवाद शामिल किए गए थे। प्रार्थी के वकील ने इस तथ्य को अब भी प्रतिकूल किया, जबकि अदालत ने यह उचित समझा कि जाँच प्रक्रिया का मौद्रिक रिकॉर्ड बुलवाया जाए। कुछ रुकावटों के बाद, पूरी फ़ाइल को अदालत के सामने प्रस्तुत किया गया, जिसमें जाँच प्रक्रिया शामिल थी। राज्य के वकील ने साबित करने के लिए मुख्य रूप से दो दस्तावेजों पर प्रमुख ध्यान दिया। जो राज्य के वकील ने दिखाया, वह फ़ाइल के पृष्ठ 109 पर है, जिसकी सच्ची अनुवादित प्रतिलिपि प्रारूप ने प्रार्थी द्वारा अभिलेख P-13 के रूप में प्रस्तुत की गई है। इसमें 12 जनवरी, 2006 को हुई जाँच प्रक्रिया की रिकॉर्ड है। इसमें दोषी अधिकारी और प्रस्तुति करने वाले व्यक्ति की उपस्थिति को दर्ज किया गया था। उसके बाद, जाँच अधिकारी ने दोषी अधिकारी से पूछा, क्या उसने उस पर लगाए गए आरोपों को स्वीकार किया। जैसा कि दर्ज किया गया था, प्रार्थी ने आलेखन के अनुसार उत्तर दिया कि आरोपों को असत्य ठहराया गया है। इसके अलावा, प्रार्थी ने यह कहा कि जाँच प्रक्रिया के दौरान जारी रखने का आग्रह किया था जब कि एक आपत्ति ने एक आपत्ति की घड़ी के दौरान क्रिमिनल प्रक्रिया के दौरान उसके खिलाफ कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रार्थी ने एक प्रतिनिधि द्वारा प्रतिष्ठानित होने के लिए इस पर प्राप्त दक्षता के लिए प्रार्थना की। प्रार्थी को साक्षात्कार में संबंधित दस्तावेजों को दिखाया गया और 8 फरवरी, 2006 को सुनवाई के अगले दिन के रूप में निर्धारित किया गया।

(9) 8 फरवरी, 2006 को, कोई प्रक्रिया दर्ज नहीं की गई है। हालांकि, फ़ाइल की रिकॉर्ड के अनुसार, उस दिन ए.एस.आई. सी.आई.डी का एक बयान उपलब्ध है जिसका संदृश्य है कि इस तिथि पर रिकॉर्ड किया गया था। फ़ाइल के रिकॉर्ड पर एक पत्र है जिसमें प्रस्तुति करने वाले व्यक्ति ने 1 फरवरी, 2006 को सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस. क्राइम इन्वेस्टिगेशन, मधुबन हरियाणा, को लिखा था, जिसमें उससे कहा गया था कि उसे 8 फरवरी, 2006 को होने वाली जाँच प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया था। इस संबंध में फ़ाइल पर एक संवाद की प्रतिलेख है जिसमें प्रार्थी ने मामले की अवलंबन में स्वास्थ्य नहीं रहने के कारण 8 फरवरी, 2006 को न्यायालय के लिए निर्धारित किए जाने के लिए प्रार्थना की थी। इस संवाद के साथ ही एक चिकित्सा रिकॉर्ड समर्थन है। इसके बाद, जाँच अधिकारी ने प्रार्थी को 16 फरवरी, 2006 को पत्र लिखा, जिसमें कहा गया था कि उसने 8 फरवरी, 2006 को उपस्थित नहीं होने पर निर्णय लिया था। जाँच अधिकारी ने फिर 16 फरवरी, 2006 को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने प्रदर्शित किया कि पिछले फरवरी 8, 2006 को प्रदर्शन नहीं किया गया था। इस संबंध में इस संवाद की पुष्टि इस संबंध में एक फैक्स संदेश के प्राप्ति के साथ इस संवाद में की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि प्रस्तुत करने वाले अधिकारी ने प्रतिवाद को दर्ज करने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन जाँच अधिकारी ने बजाय इसके कि वह प्रतिवाद को दर्ज करेंगे, उन्होंने 28 फरवरी, 2006 को अगले सुनवाई की तारीख तय की। इसके बाद प्रदर्शन नहीं करने की स्थिति में पिछले को जितना है, इसे माना जाना होगा कि यदि वह प्रतिवाद में कुछ कहना नहीं है, तो यह स्वीकृत होगा।

(10) 28 फरवरी, 2006 को कोई जाँच प्रक्रिया दर्ज नहीं की गई। इस संबंध में जिस कम्युनिकेशन की जा रही है, उसके अलावा फ़ाइल में इस संबंध में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। प्रतित्वादी ने 28 फरवरी, 2006 को प्रदर्शन नहीं किया है क्योंकि इसे जाँच रिपोर्ट में ऐसा ही उल्लेख है। हालांकि, कोई प्रक्रिया के संबंध में रिकॉर्ड तैयार नहीं किया गया था। इसके बाद, जाँच अधिकारी ने 10 मार्च, 2006 को जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की बिना किसी और साक्षात्कार या पेटीशनर को किसी भी और संदर्भ के बिना मौका देने के। यहाँ तक कि यह भी नहीं दिखाया गया है कि जाँच अधिकारी ने पिछले दिन प्रतिवादी के खिलाफ आगे बढ़ने का निर्णय किया था।

(11) जिस तरह से जाँच की गई है, उसमें बहुत कुछ चाहिए रह गया है। जाँच अधिकारी ने यह तर्क दिया जा सकता है कि पिछले मामले के प्रवेश के दौरान पिछले को जाँच के दौरान विलम्ब न करने का अधिकार था, लेकिन फिर भी उसे यह अधिकार था कि पिछले को यह सुनिश्चित करना था कि पिछला को विलम्ब न करते हुए भी पेटीशनर को न्यायपूर्वक सुनिश्चित करना चाहिए था। पेटीशनर ने 12 जनवरी, 2006 को जाँच अधिकारी के सामने प्रदर्शन किया था, जब प्रक्रिया को 8 फरवरी, 2006 को स्थगित किया गया था। यदि पेटीशनर उस तारीख पर प्रदर्शन नहीं करता, तो जाँच अधिकारी को यह करने का अधिकार था कि वह मामले को एक्स पार्टे प्रक्रिया में बढ़ावा करे या यदि उसने उपस्थित होने वाले साक्षात्कार की साक्षात्कार करने का निर्णय किया था।

(12) जाँच का तरीका जो रखा गया है, उसमें बहुत कुछ चाहिए रह गया है। जाँच अधिकारी ने शायद सही देखा है कि पेटीशनर जुर्माने के दौरान जाँच की अनुमति हासिल करने का हकदार नहीं था, लेकिन उसे पेटीशनर को सुनिश्चित करने का अधिकार था कि वह उसे सुनिश्चित करने के लिए योग्य अवसर दे। पेटीशनर ने 12 जनवरी, 2006 को जाँच अधिकारी के सामने प्रदर्शन किया था, जब प्रक्रिया को 8 फरवरी, 2006 को स्थगित किया गया था। यदि पेटीशनर उस तारीख पर प्रदर्शन नहीं करता, तो जाँच अधिकारी को यह करने का अधिकार था कि वह मामले को एक्स पार्टे मोड़ पर प्रक्रिया करे या यदि उसने उपस्थित होने वाले साक्षात्कार की साक्षात्कार करने का निर्णय किया था। प्रश्नीय ने समय बढ़ाने का अनुरोध किया था आर्थिक आधार पर। उसकी प्रार्थना को स्वीकृति मिली और मामला को 28 फरवरी 2006 को स्थानांतरित किया गया। इस संदर्भ में पेटीशनर को 16 फरवरी 2006 को सूचित किया गया। इस परिस्थिति के कारण, जांच अधिकारी की क्रिया को 8 फरवरी 2006 को साक्षात्कार करना पूरी तरह अनयायिक और नियमों का उल्लंघन था। 28 फरवरी 2006 को कोई जांच प्रक्रिया दर्ज नहीं की गई थी। उस संदर्भ में संदेह नहीं है कि पेटीशनर ने 28 फरवरी 2006 को भी प्रस्तुत नहीं होने का स्थिति में यह कहा गया है क्योंकि जांच रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। हालांकि, इस संदर्भ में कोई प्रक्रिया के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ऐसा लगता है कि जांच अधिकारी ने तब तक कोई निर्णय नहीं लिया था, जिससे यह स्पष्ट हो कि क्या जांच अधिकारी ने इस मामले में पेटीशनर के खिलाफ एक्स पार्टे प्रक्रिया आयोजित करने का निर्णय लिया था।

जब इस सूचना को स्थानांतरित करने के लिए कहा गया कि जांच अधिकारी, तो उन्होंने केवल अपने खेद प्रकट किए। उन्होंने यह भी स्वीकृत किया कि उन्हें प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी और उन्होंने प्रक्रिया के नियमों से अवगत होने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था।

(13) जांच अधिकारी इस जाँच कर रहे थे, जब उन्होंने इस जाँच में निरीक्षण करने के लिए कहा गया कि क्या उनके सामने कोई साक्षात्कार में साक्षात्कार देने के लिए साक्षात्कार किया गया था कि पेटीशनर / अपराधी अधिकारी के अभाव में किसी गवाह की कड़ी जरुरत थी। जब राज्य वकील ने इस तथ्य को खुलासा किया, उन्हें स्थिति की व्याख्या करने के लिए कहा गया था। जांच अधिकारी ने यह स्वीकृत किया कि 8 फरवरी 2006 को प्रोसीडिंग्स का कोई रिकॉर्ड तैयार नहीं किया गया था 8 फरवरी 2006 को मामले में एक्स पार्ट प्रक्रिया आयोजित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया था। यह स्थिति है कि विभाग के लिए एक सीनियर अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया था, जिससे विभाग के लिए समग्र उत्तराधिकार का कारण हुआ है। इस अज्ञान और उनकी ओर से प्रक्रिया के नियमों से अवगत नहीं होने की तरह इस परिणाम से विभाग के लिए समग्र शर्मिंदगी है। उन खिलाफ उचित कार्रवाई करना विभाग की जिम्मेदारी है क्योंकि वह उस खामी के लिए जिम्मेदार है।

(14) नियमित प्रक्रिया और एक कड़ी निर्धारित की गई प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता को जोर नहीं दिया जाना चाहिए। इसे देखा गया है कि प्रक्रियाशास्त्रिय सुरक्षाओं को शक्ति के स्वीप के साथ संगत किया जाना चाहिए। शक्ति ज्यादा हो, तो उसके उपयोग में संयम की अधिक आवश्यकता है और योग्य रूप से, ऐसे सांविदानिक सुरक्षा का विचार किया जाना चाहिए जो ऐसे अधिनियम द्वारा जिसे वह अपने क्रियावली को जज्ज्बा दिखाता है।विटारकेली बनाम सीटन, आंतरिक सचिव (1) में यह दृष्टांत दिया गया था कि किसी कार्यकारी एजेंसी को उन मानकों से कड़ाई से बाधित किया जाना चाहिए, जिनके आधार पर इसे अपने क्रियावली को मूल्यांकित किया जाना चाहिए। सुरक्षा और एक्सचेंज कॉमन बनाम चेंसरी कॉर्प (2) देखें। इस प्रकार, यदि रोजगार से निकालना किसी परिभाषित प्रक्रिया पर आधारित है, यह भला होता है या उस संगठन को बाँधने वाली आवश्यकता से भी बहुत विस्तार से, उस प्रक्रिया का सूचना से पालन किया जाना चाहिए। सर्विस बनाम डल्स (3) देखें। इसे और भी देखा गया है कि "यह न्यायिक रूप से विकसित शासन का यह नियम अब मजबूती से स्थापित है और, यदि मैं जोड़ सकता हूं, सही भी।' यह भी देखा गया है कि "वह, जो प्रक्रियात्मक तलवार लेता है, वह उसी तलवार के साथ मर जाएगा।' आज़ादी का इतिहास बड़े हिस्से में प्रक्रियात्मक सुरक्षाओं का अनुसरण का इतिहास रहा है। इस प्रक्रियात्मक सुरक्षा के महत्व के कारण, जब सेवा का अंत गंवारा जाता है, तो प्रक्रिया का पालन समर्पित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

(15) प्रमुख दंड लगाने के लिए जांच करने की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है नियम 7 के अनुसार। इस नियम में प्रदान किया गया है कि इस नियम के अनुप्रयोगी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी प्रमुख दंड लगाने का आदेश नहीं किया जाएगा जब तक उसे उसके खिलाफ

उठाई जाने वाली कार्रवाई का कारण दिखाने का एक उचित अवसर नहीं मिला है। उस व्यक्ति से संबंधित प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए उपायुक्त प्रावधान किए जाते हैं जो मुख्य दंड लगाने के लिए आरोपित होता है। व्यक्ति को लिखित में यह कहने के लिए उचित समय दिया जाता है कि क्या वह सभी या किसी आरोपों के सच्चाई को स्वीकार करता है और उसकी रक्षा के लिए यदि कोई है, तो उसका क्या कारण है। दोषी कर्मचारी से यह भी पूछा जाता है कि क्या वह व्यक्तिगत रूप से सुनना चाहता है। अगर प्रमुख दंड लगाने की कोई भी आवश्यकता है तो आधिकारिकों द्वारा जो उदाहरण रूप से व्यक्त किया गया है या जिनका उदाहरण रूप से व्यक्त किया गया है, वह सभी सूचना के रूप में सुनी जाएगी जो स्वीकृत नहीं हैं। आपत्ति रखी जाने पर व्यक्ति को साक्षात्कार करने, साक्षात्कार में साक्षात्कार करने और जो गवाह हो सकते हैं, उन्हें बुलाने का अधिकार है, प्रदान किया जाता है, परंतु यदि आधिकारी ने लिखित रूप से तथा किसी गवाह को बुलाने से मना कर दिया है, तो किसी भी साक्षात्कार की योजना हो सकती है। महत्वपूर्ण रूप से, प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियम 7 में दी गई विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है, जिसका नियमित पालन किया जाना अनिवार्य है। जांच अधिकारी ने नियम 7 में दी गई प्रक्रिया का पालन नहीं किया और स्पष्ट रूप से आरोपी कर्मचारी को उसकी रक्षा के लिए कोई अवसर नहीं दिया। जो साक्षात्कार किया गया था, वह पेटीशन की अनुपस्थिति में था और उसे अपनी रक्षा करने या उसकी अनुपस्थिति में लेदी गई प्रमाण की आपत्ति करने का भी कोई अवसर नहीं दिया गया था। पेटीशनर की अनुपस्थिति में प्रमाण को रिकॉर्ड करने के लिए, जांच अधिकारी को पहले एक निर्णय लेना था कि वह एक्स पार्टे प्रक्रिया आगे बढ़ने का निर्णय लेता है, जो कभी नहीं हुआ था। बल्कि 8 और 28 फरवरी 2006 के लेन-देन के बारे में कोई प्रक्रिया का रिकॉर्ड कभी नहीं किया गया था। यह नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन है और इस उल्लंघन के परिणामस्वरूप पेटीशनर के लिए गंभीर नागरिक परिणाम हुआ है। पेटीशनर को इस जांच और फैसले के आधार पर सेवानिवृत्ति कर दिया गया है और नियमों के तहत अनिवार्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा का पालन नहीं किया गया है, जिससे इस विवादित आदेश को उस कारण बुरा साबित किया जा सकता है और इसे इसलिए नहीं बनाए जा सकता है।

(16) उस सवाल की अगली विचारणीय चीज यह होगी कि प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण पेटीशनर को कौन-कौन से प्रकार की राहत मिलेगी।

(17) पेटिशनर के खिलाफ लगाए गए आरोप बहुत गंभीर हैं। प्रतिष्ठान में प्रवेश करने का आरोप है कि पेटिशनर ने एक जाली डिप्लोमा और डिग्री के आधार पर सेवा में प्रवेश किया। यदि यह सच है, तो निश्चित रूप से इस धांधले का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यह कि जांच अधिकारी ने जांच को ठीक और न्यायपूर्ण तरीके से करने में दोष किया है, केवल इसका परिणाम नहीं हो सकता कि किसी को एक जाली या झूठे डिग्री के आधार पर सेवा में जारी रखा जाए। पेटिशनर के खिलाफ एक कठोर धांधले का मुद्दा है, तो उसे अनदेखा करने की अनुमति देना सही नहीं है, सिर्फ इस कारण कि इस खिलाफ उपाय के लिए पितृ ने एक

प्रक्रियात्मक सुरक्षा का हक प्राप्त किया हो सकता है। परिस्थितियों के दृष्टिकोण से, प्रतिष्ठान और पेटिशनर दोनों के लिए न्यायपूर्ण होने के लिए उचित होगा कि प्रतिस्थानीय अधिकारियों को इस प्रक्रिया के स्थान से जांच करने की अनुमति दी जाए और पेटिशनर को उसकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त और न्यायपूर्ण अवसर दिया जाए। प्रतिष्ठानीय अधिकारीयों को पेटिशनर के खिलाफ लगे गए आरोपों का समर्थन करने के लिए किसी भी साक्षायिक साक्षायिक प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। पेटिशनर को अनुमति दी जाएगी कि विधि के अनुसार क्रियावली जारी करें उसके पास मानवाधिकारों और न्याय के सिद्धांत पर आधारित तथा स्वतंत्र रूप से उनकी रक्षा करने के लिए। यह उस पद्धति है, जो सुप्रीम कोर्ट ने मैनेजिंग डायरेक्टर, ईसीआईएल, हैदराबाद और अन्य बनाम बी. कारुणाकर और अन्य (4) में विचार करते समय स्पष्ट रूप से उपलब्ध किया है। थोड़ी सी समान स्थिति के साथ निपुण होकर, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के मामलों में किस प्रकार की सहारा देने चाहिए, इस पर जाएवाल के प्रश्न में गया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, इसका उत्तर दीना होगा यदि दंड को ध्यान में रखते हुए करीब दंडित कर दिया जाता है कि जांच को विरोधित कारणों ने कर्मचारी को गंभीरता से नुकसान पहुंचाया है। कुछ मामलों में उल्लंघन से कोई भेद नहीं हो सकता है जो अंत में प्रदान किया जाने वाला दंड को। इस प्रकार, यह देखा गया है कि यदि उल्लंघन से कोई भिन्न परिणाम नहीं होता है, तो एक कर्मचारी को कर्मचारी को कर्मस्थल पर पुनर्स्थापित करने और सभी परिणामस्वरूप लाभ प्राप्त करने की अनुमति देना न्याय के नियमों को एक सांविदानिक रीति में कम करने के समान होगा। जैसा कि दृष्टिकोण और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का विस्तार किया जा रहा है, यह न्याय के नियमों को एक यांत्रिक अनुष्ठान में बदलना है। जैसा कि यह अवलोकन किया जाता है, यह न्याय के सिद्धांत और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को स्थायी रूप से बनाए रखने और व्यक्ति को उसके न्यायपूर्ण अधिकारों की स्थापना करने में सहायक करने के लिए बनाए गए हैं। इन्हें उत्पन्न करने या सभी और अन्य समयों पर प्रदर्शन करने के लिए आवाहन किए जाने वाले कोई मंत्र नहीं हैं। यह देखने के लिए है कि क्या कर्मचारी को कहीं नुकसान पहुंचाया गया है या नहीं, हर मामले के तथ्य और परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए। जहां यह देखा जाता है कि उल्लंघन से कोई भिन्न परिणाम नहीं होगा, वह किसी कर्मचारी को कर्तव्य पर लौटने और सभी सहायक लाभ प्राप्त करने की अनुमति देना न्याय को असहज और अनुचित सीमाओं तक बढ़ाने के समान है। अदालत ने यह भी देखा है कि इससे यह धन्यवाद और दोषी को पुरस्कृत करने के समान है और, इस प्रकार, न्याय के सिद्धांत को अयोग्य और उत्साहजनक सीमाओं तक बढ़ाने का प्रयास है। यह न्याय के सिद्धांत का एक अस्वाभाविक विस्तार है, जो खुद में न्याय के लिए अनैतिक है।

(18) पेटिशनर के खिलाफ खड़ा आरोप देखकर, उसके पुनर्स्थापन की दिशा देना धूर्तता की प्रशंसा करने के समान होगा, जिससे न्याय के सिद्धांत को अत्याचारपूर्ण और अन्यायपूर्ण सीमाओं तक खींचा जा सकता है। इसलिए, इसे आवश्यक नहीं माना जाता कि सजा का आदेश सेट-एसाइड होने पर भी पुनर्स्थापन की दिशा दी जाए। जैसा कि मैनेजिंग डायरेक्टर, ईसीआईएल,

हैदराबाद (उपरोक्त) में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, इस प्रकार के मामलों में उचित सहारा हमेशा ऐसा होना चाहिए कि प्राधिकृति/प्रबंधन को कर्मचारी को निलंबित करके जांच करने का अधिकार होता है और उसे उसी स्थिति से शुरू करके जारी रख सकता है जहां कमी पता चली है। कर्मचारी को पुनर्स्थापित करने की आदेश देने पर भी, यदि अंत में ऐसा होता है, तो प्रशासनिक अधिकारियों को कानून के अनुसार उस समय के बाद की प्रक्रिया के समापन पर निर्भर करना होगा और अंतिम परिणाम के आधार पर कर्मचारी को बैक वेज और अन्य लाभ की अधिकतम मात्रा का निर्णय लेने का अधिकार होगा। यदि कर्मचारी नई जांच में सफल होता है और पुनर्स्थापित करने का आदेश होता है, तो प्राधिकृति को कैसे देखभाल करेगी, इस पर निर्भर करना होगा, और उसे कौन-कौन से लाभ, यदि कोई हो, और उसकी मात्रा का निर्धारण करने का अधिकार होगा। जांच की नई मुखायिका में पुनर्स्थापन को इस रूप से स्वीकृत किया जाना चाहिए कि यह नई मुखायिका की होने वाली है और कहीं अधिक नहीं जहां ऐसी नई मुखायिका की जाएगी। इसे मैनेजिंग डायरेक्टर, ईसीआईएल, हैदराबाद (उपरोक्त) द्वारा कानून में सही स्थिति के रूप में नोट किया गया है।

(19) इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए, पेटिशनर को सजा देने वाला विवादित आदेश सेट-एसाइड किया जाता है। प्रतिस्पर्धी को गवाहों को परीक्षित करने के लिए बुलाया जाने वाले चरण से परायण करने की अनुमति दी जाती है। इस उद्देश्य के लिए, पेटिशनर को सेवा में पुनर्स्थापित किया जाने की आवश्यकता नहीं है और उसे उसे ताजगी के साथ पुनर्स्थापित किया जाएगा, ताकि इसे अब होने वाले नए जांच के लिए स्थिति में रखा जा सके। किसी अन्य पथ के अनुसरण से, यह पेटिशनर को उसकी ईमानदारी से सेवा में प्रवेश करने के गंभीर दोष पर प्रीमियम देने का एक योजना में योगदान करेगा। पेटिशनर के अधिकार का निर्णय आज़रू की जांच के अंतर्गत होने वाले परिणाम पर निर्भर करेगा।

(20) इस प्रकार, यह रिट पिटीशन उपरोक्त शर्तों में निर्णयित होती है।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

भुवनेश सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

नारनौल, हरियाणा